

ममता बनर्जी गिरफ्तार हो सकती हैं, ईडी की कार्रवाई में बाधा डालने के आरोप में

ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी व प.बंगाल की पुलिस के खिलाफ अन्ततोगत्वा मुकदमा दर्ज किया

-अंजन राॅय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 12 जनवरी। एन्कोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ईडी) ने अन्ततोगत्वा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उन राज्य पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मामले दर्ज करवा दिए हैं, जो कोलकाता में प्रतीक जैन के आवास और आई-पैक के कार्यालयों पर हुई ईडी की छापेमारी के दौरान वहां पहुंचे थे।

ईडी ने ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल पुलिस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। यदि ये मामले अदालत में कायम रहते हैं, तो इससे उनकी तत्काल गिरफ्तारी संभव हो सकती है। पूरे देश में यह एक अभूतपूर्व घटना मानी जा रही है कि किसी सत्तारूढ़ मुख्यमंत्री ने छापेमारी और जांच प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया हो।

ईडी ने राज्य की मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिनमें महत्वपूर्ण सबूतों को नुकसान पहुंचाने

- अगर, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की शिकायत को स्वीकार करते हुए निर्णय सुनाया तो ममता बनर्जी को सीधे जेल जाना पड़ेगा।
- ईडी ने सीबीआई से पूरे प्रकरण की जाँच कराने की भी मांग की है।
- दूसरी और पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष “केविट” फाइल की, सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई भी निर्णय लेने से पहले राज्य सरकार का पक्ष भी सुने।
- जैसा कि विदित ही है, कंसलटेंसी कंपनी आई-पैक, जिसके ऑफिस पर ईडी ने रेड की, ने 2021 के प.बंगाल विधानसभा चुनाव और उसके बाद भी तृणमूल कांग्रेस की चुनाव की रणनीति फाइनल करने में अहम् भूमिका निभाई थी। प.बंगाल की मु.मंत्री ममता बनर्जी ने सार्वजनिक मंच से, आई-पैक के दफ्तर पर रेड के दौरान वहाँ पहुंचने और फाइलें ले जाने को सही बताते हुए कहा कि ईडी की रेड राजनीति से प्रेरित है।

और जांच में बाधा डालने के आरोप शामिल हैं।

गत सप्ताह ईडी ने आई-पैक के कार्यालयों और उसके स्थानीय प्रमुख प्रतीक जैन के आवास पर रेड की थी। रेड के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मौके पर पहुँचीं और कथित तौर पर वहां से महत्वपूर्ण सबूत अपने साथ ले गईं।

ईडी एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के लीज क्षेत्र से कोयले की चोरी और उसे चुनिंदा खरीदारों को बेचने से जुड़ी शिकायतों की जांच कर रही है। इस अवैध आय को हवाला चैनलों के जरिए बाहर भेजा गया और बाद में वापस लाया गया। ईडी पहले ही हवाला लेनदेन को लेकर गंभीर आरोप लगा चुकी है और

उसके पास इससे जुड़े अहम सबूत और जानकारी मौजूद हैं।

कानून के तहत किसी जांच एजेंसी की रेड में हस्तक्षेप करना एक संज्ञेय अपराध है। किसी लोक सेवक के कार्य में बाधा डालना कानून का उल्लंघन माना जाता है और इसमें हस्तक्षेप करने (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अस्पताल में भर्ती

धनखड़ शनिवार 10 जनवरी को बाथरूम में लगातार दो बार बेहोश हो गए

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 12 जनवरी। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को सोमवार को नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (ऑल इण्डिया इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़-एम्स) में भर्ती कराया गया।

अधिकारियों के अनुसार, वे सप्ताहांत में दो बार बेहोश हो गए थे।

74 वर्षीय धनखड़ को 10 जनवरी को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हुई थीं, जिसके बाद उन्हें एम्स ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने आगे की जांच के लिए उन्हें भर्ती करने का फैसला किया।

धनखड़ ने पिछले वर्ष 21 जुलाई को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था।

उनका इस्तीफा अचानक आया था और इसके बाद कई अटकलें लगाई गईं।

इस्तीफे के बाद, वे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बहुत ही कम दिखाई दिये।

- सोमवार सुबह उन्हें जाँच के लिए एम्स ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर्स ने उन्हें भर्ती कर लिया। यहाँ एमआरआई सहित उनकी सभी जाँचें की जाएंगी।
- धनखड़ पिछले दिनों कई बार बेहोश हो चुके हैं। कच्छ के उत्तराखंड, केरल और नई दिल्ली में हुए कार्यक्रमों में भी उन्हें बेहोशी का दौरा पड़ा था।
- धनखड़ ने गत वर्ष खराब स्वास्थ्य के कारण अचानक उपराष्ट्रपति के पद से त्याग पत्र दे दिया था, उसके बाद कई तरह की अटकलें लगाई गईं और उनकी सार्वजनिक मौजूदगी भी कम हो गई थी।

स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी साझा करते हुए अधिकारियों ने बताया कि शनिवार को जब वे वांशरूम गए थे, तब उन्हें “दो बार बेहोशी” के दौरे पड़े। इसके बाद उन्हें चिकित्सकीय जांच की सलाह दी गई।

एक अधिकारी ने कहा, “आज वे जांच के लिए एम्स गए थे, लेकिन

डॉक्टरों ने जाँचों के लिए उन्हें भर्ती करने पर जोर दिया।

अधिकारियों ने बताया कि मेडिकल टैस्टों के तहत, डॉक्टरों द्वारा एमआरआई किए जाने की संभावना है।

एक अधिकारी के अनुसार, हाल के दिनों में विभिन्न सार्वजनिक (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मुख्यमंत्री ने लोहड़ी व मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दीं

जयपुर, 12 जनवरी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लोहड़ी एवं मकर संक्रांति के पावन पर्व पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। शर्मा ने कहा कि बंसत ऋतु के आगमन और नई फसल के उल्लास में मनाया जाने वाला पर्व लोहड़ी प्रकृति

- उन्होंने प्रदेशवासियों को जरूरतमंदों की मदद का संकल्प लेने के लिए कहा।

के प्रति हमारी आस्था का प्रतीक है। उन्होंने कामना की कि लोहड़ी की पावन अग्नि प्रदेशवासियों के जीवन से नकारात्मकता को दूर कर स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रकाश फैलाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान सूर्य देव के उत्तरायण होने के अवसर पर मनाया जाने वाला पर्व मकर संक्रांति हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। यह पर्व हमारे देश की समृद्ध विरासत और सांस्कृतिक एकता (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ट्रंप बने वेनेज़ुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति!

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 12 जनवरी। सोशल मीडिया पर डाली गई एक तस्वीर, जो एडिट किए गए विकिपीडिया पेज जैसी दिखती है, में ट्रंप को आधिकारिक फोटो लगाकर उन्हें “वेनेज़ुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति” बताया गया है। असल विकिपीडिया पेज पर ट्रंप को वेनेज़ुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं बताया गया है और न ही किसी

- ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जारी एक फोटो में खुद को वेनेज़ुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित किया है।

अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने इस दावे को मान्यता दी है।

यह पोस्ट अमेरिका द्वारा मौजूदा वेनेज़ुएला राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़कर हटाने के बाद सामने आई। मादुरो को उनकी पत्नी के साथ न्यूयॉर्क ले जाया गया है, जहां उन्हें संघीय ड्राग तस्करी के आरोपों का सामना करना होगा। यह कार्रवाई कई महीनों से चल रहे अमेरिकी दबाव, प्रतिबंधों और तेल-समृद्ध देश के खिलाफ सैन्य गतिविधियों के बाद की गई।

मादुरो ने कहा है कि उनका (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘प्र.मंत्री मोदी व अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की दोस्ती “सच्ची” है’

अमेरिका के नवनियुक्त राजदूत सर्जियो गोर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए यह भी कहा कि सच्चे दोस्त आपस में बैठकर मतभेद सुलझा लेते हैं

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 12 जनवरी। अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप अगले साल तक भारत का दौरा कर सकते हैं। यह बात अमेरिका के नामित राजदूत सर्जियो गोर ने कही। उन्होंने यह भी बताया कि वॉशिंगटन और नई दिल्ली मंगलवार से व्यापार समझौते के अगले दौर की बातचीत फिर से शुरू करने जा रहे हैं।

गोर, जो दक्षिण और मध्य एशिया के लिए विशेष दूत भी हैं, यहां अमेरिकी दूतावास में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ ट्रंप की दोस्ती सच्ची है और सच्चे दोस्त अपने मतभेद सुलझा सकते हैं।

अपने आगमन भाषण में उन्होंने कहा, “अमेरिका और भारत केवल साझा हितों से ही नहीं, बल्कि सबसे ऊंचे स्तर पर मजबूत रिश्तों से जुड़े हैं। सच्चे दोस्त असहमति रख सकते हैं, लेकिन आखिर में अपने मतभेद सुलझा हा लेते हैं।”

- गोर ने यह भी कहा कि वॉशिंगटन व नई दिल्ली मंगलवार से “ट्रेड डील” पर वार्ता का अगला “राउण्ड” शुरू करेंगे।

- गोर ने पत्रकारों को यह भी बताया कि उनका राजदूत के रूप में नियुक्ति का मकसद दोनों देशों की “पार्टनरशिप” को और अगले स्तर पर ले जाना है तथा भारत-अमेरिका “ट्रेड डील” एक चुनौतीपूर्ण काम है, पर, वे कटिबद्ध हैं कि इस “ट्रेड डील” को पूरा करवाएंगे।

गोर ने आगे कहा, “भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है, इसलिए इस समझौते को अंतिम रूप देना आसान काम नहीं है, लेकिन हम इसे पूरा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।”

उन्होंने कहा कि हालांकि, व्यापार नई दिल्ली और वॉशिंगटन के रिश्तों के लिए बहुत अहम है, लेकिन इसके अलावा सुरक्षा, आतंकवाद विरोध, ऊर्जा, तकनीक, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं।

गोर ने जोर देते हुए कहा, “मैं राष्ट्रपति ट्रंप के साथ दुनिया भर में घूम चुका हूँ और मैं यह कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी दोस्ती “सच्ची” है।”

नामित अमेरिकी राजदूत ने कहा कि उनकी नियुक्ति का उद्देश्य दोनों देशों की साझेदारी को अगले स्तर पर ले जाना है।

उन्होंने आगे कहा, यह दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र और दुनिया के (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जोर पकड़ने लगा है मनरेगा समर्थक आंदोलन देश के विभिन्न भागों में विपक्षी दलों, खासकर कांग्रेस के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन शुरू किए गए हैं

- रविवार को वाराणसी में मनरेगा बचाओ संग्राम कार्यक्रम के तहत प्रदर्शन कर रहे एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं पर पुलिस के लाठी चार्ज की सभी तरफ से कड़ी निंदा की गई।

- मनरेगा योजना के सुजनकर्ता जीन ड्रेज ने कहा कि नई वीबी जी राम जी योजना केन्द्रीकृत है, इसमें सारी जिम्मेदारी राज्यों की है, यही नहीं, इसे जब चाहे बंद किया जा सकता है।

- अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नाम चीन अर्थशास्त्री जैसे थॉमस पिकेटी, नोबल सम्मान विजेता जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ आदि ने भी मनरेगा को खत्म किए जाने पर विरोध जताया है।

खिलाफ 45 दिनों का राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है।

शनिवार को उत्तर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, इसके बाद जिला मुख्यालयों पर एक दिवसीय उपवास और प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन किया गया। 12 से 29 जनवरी के बीच सभी

ग्राम पंचायतों में चौपालों और जनसंपर्क कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जबकि 30 जनवरी को वाई स्तर पर सभाएं होंगी। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, 7 से 15 फरवरी के बीच विधानसभाओं का राज्य स्तरीय “धेराव” किया जाएगा और 16 से 25 फरवरी के बीच चार बड़ी रैलियां

आयोजित की जाएंगी।

कांग्रेस ने रविवार को आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में मोदी-योगी डबल इंजन सरकार ने वाराणसी में शांतिपूर्ण मार्च निकाल रहे एनएसयूआई के प्रदर्शनकारियों पर बर्बर लाठीचार्ज करने का आदेश दिया। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा, “मनरेगा को खत्म किए जाने और लाखों लोगों को रोजगार के अधिकार से वंचित किए जाने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे एनएसयूआई छात्रों पर ताकत का बर्बर इस्तेमाल और गिरफ्तारियां बेहद निंदनीय हैं।

वीबी-जी-राम-जी विधेयक 18 दिसंबर को, लोकसभा में पारित होने के कुछ ही घंटों बाद, राज्यसभा में ध्वनिमत से पारित किया गया था तथा तीन दिन बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसे अपनी मंजूरी दे दी थी।

आलोचकों का कहना है कि नए कानून की असली समस्या उसकी बारीकियों में छिपी है। मनरेगा के प्रमुख सिलपकार जीन ड्रेज का कहना है कि नई (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

एसआई भर्ती पेपर लीक के चार आरोपियों को जमानत मिली

जयपुर, 12 जनवरी। राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में चार आरोपियों, कैलाश कुमार, मंगलाराम, परमेश चौधरी और विनोद कुमार जाट को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। जस्टिस विनोद

- हाई कोर्ट ने जेल में बिताई अवधि व केस की सुनवाई में लगने वाले समय को देखते हुए जमानत मंजूर की।

कुमार भारवानी की एकलपैठ ने यह आदेश चारों आरोपियों की ओर से पेश जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि प्रकरण की तथ्यात्मक स्थिति, आरोपियों की ओर से जेल में बिताई अवधि और केस की सुनवाई में लगने वाले समय को देखते हुए उन्हें जमानत (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘परीक्षा रद्द करने के टास्क के आधार पर एसआईटी ने पहली रिपोर्ट दी थी’

जयपुर, 12 जनवरी। एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में एकलपैठ की ओर से भर्ती रद्द करने के आदेश के खिलाफ खंडपीठ में सुनवाई हुई। अदालत ने मामले में चयनित अर्थार्थियों की दलीलें सुनकर मामले

- एसआई भर्ती मामले में चयनित अर्थार्थियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कमलाकर शर्मा ने दलीलें रखीं।

की सुनवाई 15 जनवरी को तय की है। एक्टिंग सीजे एसपी शर्मा और जस्टिस संगीता शर्मा की खंडपीठ ने चयनित अर्थार्थियों व अन्य की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिए।

चयनित अर्थार्थियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कमलाकर शर्मा ने (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विचार बिन्दु

चापलूसी का ज़हरीला प्याला आपको तब तक नुकसान नहीं पहुँचा सकता जब तक कि आपके कान उसे अमृत समझ कर पी न जाएँ। —प्रेमचंद

एस आई आर पर घमासान

किसी भी लोकतंत्र की पहचान यही है कि वहां पर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव नियमित रूप से हों एवं बहुमत प्राप्त दल सरकार बनाकर शासन प्रदान करे। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के वैसे तो बहुत सारे आयाम हैं किंतु मूल आधार सही मतदाता सूची का होना है । इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक उस व्यक्ति का नाम इसमें दर्ज होना चाहिए जो मतदान करने का अधिकारी है एवं ऐसे किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं होना चाहिए जो मतदान का अधिकारी नहीं है ।

चुनाव कराने की जिम्मेदारी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3२4 के अंतर्गत भारत के निर्वाचन आयोग को दी गई है। मतदाता सूचियों का अद्यतन (अपडेट)करने हेतु समय-समय पर निर्वाचन आयोग मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण करता रहा है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य उन सभी व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची से हटाना होता है जिनकी मृत्यु हो जाती हैअथवा जो स्थाई रूप से कहीं और निवास करने लग गए हों।

इन स्थापित प्रक्रियाओं को छोड़कर निर्वाचन आयोग ने अचानक जून 2025 में बिहार के चुनाव से लगभग तीन माह पूर्व मतदाता सूचियों के सघन गहन परीक्षण अर्थात एस आई आर की प्रक्रिया के बारे में आदेश जारी कर दिए । यह उल्लेखनीय है कि गत 23 वर्षों में यह प्रक्रिया कहीं नहीं की गई थी। इसका कारण मतदाता सूचियों का डिजिटइजेशन होना था। इसका उद्देश्य घुसपैठियों के नामों को मतदाता सूचियों से हटाना था । विपक्षी दलों द्वारा इसका भरपूर विरोध करने एवं ‘वोट चोरी’ यात्रा निकालने के बावजूद निर्वाचन आयोग ने इसे नहीं रोका और एस आई आर के बाद की मतदाता सूची के आधार पर बिहार के चुनाव संपादित करना लिए । कुछ दल एवं सामाजिक कार्यकर्ता सर्वोच्च न्यायालय में गए किंतु उन्हें वहां से कोई राहत नहीं मिली । न्यायालय द्वारा इस प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई गई। नवंबर में इस मतदाता सूची के आधार पर हुए चुनावों में भारी बहुमत से एनडीए की सरकार बन गई और नीतीश कुमार पुनः मुख्यमंत्री बन गए । बिहार में शांतिपूर्वक हुए चुनाव को निर्वाचन आयोग इस बात की पुष्टि मान रहा है कि उनके द्वारा की गई प्रक्रिया सही थी और उसने 1२ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एस आई आर प्रारंभ करने की घोषणा कर दी। इसका भारी विरोध हुआ, विशेषकर पश्चिम बंगाल सरकार और वृणमूल कांग्रेस द्वारा। इस प्रक्रिया के बारे में सर्वोच्च न्यायालय में भी कई बार सुनवाई हुई लेकिन अभी तक इस बारे में कोई प्रभावी कार्रवाई न्यायालय द्वारा नहीं की गई है। निर्वाचन आयोग ने तो आधार को 11 दस्तावेजों के साथ 1२ मवें दस्तावेज के रूप में स्वीकार करने की न्यायालय की सलाह को भी नहीं माना और अभी भी उसे मान्य दस्तावेज के रूप में सम्मिलित नहीं किया है।

इस बात की एस आई आर में अन्य राज्यों के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश भी सम्मिलित है। यहां एस आई आर के पहले की मतदाता सूची में 1५.44 करोड़ मतदाता थीं। ड्राफ्ट सूची जारी करने के लिए कई बार समय बढ़ाने के बाद जब अंतिम ड्राफ्ट सूची जारी की गई तो इसमें यह संख्या घटकर 1२.५५ करोड़ रह गई।

यह उल्लेखनीय है कि जिन व्यक्तियों के नाम पूर्वी की मतदाता सूची में थे उन्हें गणना प्रपत्र बांटे गए और उनसे भरवा कर पुनः लिए गए। प्रत्येक मतदाता को उनका या रिश्तेदार का नाम २00३की मतदाता सूची में सम्मिलित होने का प्रमाण भी देना था। यह प्रपत्र कुल १२.५५ करोड़ लोगों से प्राप्त हुए, अर्थात २.८९ करोड़ के नाम कट गए। इन १२.५५ करोड़ में भी १.०४ करोड़ ऐसे हैं जिन्होंने फार्म तो भरकर निर्वाचन आयोग में जमा कर दिए, किंतु उनको मैपिंग अभी तक नहीं हुई है। अर्थात उनका स्वयं का या रिश्तेदार का नाम २००३ की मतदाता सूची में नहीं मिल पाया है । यदि इनकी मैपिंग ना हो पाए तो मतदाता सूची में अंकित मतदाताओं की संख्या १२.५५ करोड़ से घटकर ११.५१ करोड़ रह जाएगी। मैने इसी संक्षेप में चार बार एस आई आर के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से लिखा था, किंतु जिस प्रकार के चौकाने वाले आंकड़े उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं और जो समाचार वहां से मिले हैं उसके आधार पर पाठकों की आंखों को विश्लेषण के साथ प्रस्तुत करना उचित लगा ताकि वे स्वयं यह निर्णय कर सकें कि एस आई आर का उद्देश्य क्या था और उससे क्या हासिल हो पाया है? यहां तक निर्वाचन आयोग एवं सर्वोच्च न्यायालय का प्रश्न है वे तो, सभी प्रकार की विसंगतिया सामने आने के बाद भी धृतराष्ट्र की तरह आँखें मूंद कर बैठे हैं ।

यह बात कई बार कही जा चुकी है कि किसी का नाम एक से अधिक जगह दर्ज होने, उसके मृत होने या अन्य कहीं चले जाने के बाद उसका नाम हटाने का कार्य तो सामान्य पुनरीक्षण प्रक्रिया में हमेशा संभव था। उसके लिए एस आई आर पर करोड़ों रुपए खर्च करने और सबको परेशान करने की आवश्यकता नहीं थी। २००३ की मतदाता सूची में नाम ढूँढने का काम लोगों के लिए

बहुत परेशानी का कारण बना है और बी एल ओ तक भी ऐसा नहीं कर पाए हैं । इसी लिए उत्तर प्रदेश में १.०४ करोड़ मतदाता अभी भी unmappped है।

पाठकों को शायद यह विदित हो कि पंचायती राज और स्थानीय निकाय के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा और लोकसभा के कराए जाते हैं । उत्तर प्रदेश के जिस निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची, जिसे अंतिम रूप हाल ही में दिया गया है, उसमें केवल ग्रामीण क्षेत्र के मतदाताओं की संख्या १२.६९ करोड़ है ,जबकि एस आई आर की ड्राफ्ट मतदाता सूची में पूरे राज्य में १२.५५ करोड़ लोगों का नाम है । राज्य निर्वाचन आयोग के ठाामीण मतदाता सूची में यदि शहरी मतदाताओं की संख्या जोड़ दी जाए तो राज्य के कुल मतदाताओं की संख्या लगभग १७ करोड़ होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि एक ही राज्य में विधानसभा/लोकसभा के लिए १२.५५ करोड़ मतदाताओं की तुलना में पंचायती राज

और नगर निकायों के चुनाव में १७ करोड़ लोग मतदान करेंगे । यह ४.५० करोड़ का अंतर समझ से परे है। वहां तक विदेशी अवैध लोगों को मतदाता सूची से बाहर निकालने का प्रश्न है, बिहार में पूरी प्रक्रिया के बावजूद अभी तक निर्वाचन आयोग ने यह सार्वजनिक नहीं किया है कि कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें विदेशी होने के कारण मतदाता सूची से हटाना गया।

उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में कहा कि चार करोड़ लोगों के नाम कटे हैं जिनमें से अधिकांश भाजपा के हैं। उन्होंने आब्धान किया कि प्रत्येक वृथ पर १५०-२०० लोगों के नाम जुड़वाने हैं। योगी आदित्यनाथ के इस कथन के बाद समाजवादी पार्टी ने निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया को सही बताया, शायद इसलिए कि बीजेपी के मतदाताओं के नाम कटे हैं । प्रश्न यह नहीं है कि एस आई आर के कारण किस दल को लाभ होगा अथवा हानि होगी, बल्कि यह है कि जो कार्य किया जा रहा है वह कितना न्यायोचित एवं मतदाताओं के लिए सुविधाजनक है? किसी भी ग्रामीण गरीब मतदाता से अपेक्षा करना कि वह अपने दस्तावेज प्राप्त करने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाएगा, सही नहीं है।

एस आई आर के निर्देशों के अनुसार जिन व्यक्तियों के नाम इन १२.५५ करोड़ की ड्राफ्ट सूची में सम्मिलित नहीं है उन्हें नए वोटर बनने के लिए फॉर्म ६ भरना पड़ेगा। यह किन्ती विचित्र बात है कि जो व्यक्ति लगातार कई चुनाव में वोट दे रहे थे उन्हें पुनः नए वोटर की तरह दस्तावेज चुनाव आयोग में जमा करने होंगे। २००३ में हुए एस आई आर के बाद मतदाता सूचियों का कंप्यूटरीकरण कर दिया गया था। उसके बाद इस प्रकार की कार्रवाई की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि केवल एक बटन दबाकर एक से अधिक स्थान पर दर्ज मतदाताओं के नामों को आसानी से काटा जा सकता था ।

मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया स्पष्ट और पारदर्शी होनी चाहिए ।उत्तर प्रदेश में और अन्य राज्यों में जिस प्रकार से एस आई आर किया जा रहा है वह न केवल अस्पष्ट अपितु अपारदर्शी भी है । इसके कारण कई प्रकार की आशंकाओं को बल मिलना स्वाभाविक है। चुनाव न केवल स्वतंत्र और निष्पक्ष हों अपितु जनता में यह विश्वास होना भी आवश्यक है। यही सबसे बड़ी कमी इस एस आई आर की प्रक्रिया में दिखाई दे रही है।

यदि १.०४ करोड़ लोगों का मैपिंग नहीं हो पता है तो मतदाता सूची में कुल संख्या लगभग ११.५१ करोड़ रह जाएगी जो राज्य निर्वाचन सूची में दर्ज मतदाताओं के मुकाबले में ५.५ करोड़ कम होगी । इस प्रकार लगभग ३० प्रतिशत मतदाताओं की संख्या में कमी आना आश्चर्य जनक है। सामान्यतः आजकल चुनाव में हार जीत का अंतर एक या दो प्रतिशत होता है। यदि मतदाताओं की संख्या में २०-३० प्रतिशत मतदाताओं का अंतर आ जाए तो इसका कितना प्रभाव चुनावी परिणाम पड़ सकता है, उसका अनुमान ही लगाया जा सकता है।

जनसंख्या में १८ वर्ष की आयु के ऊपर के लोगों का प्रतिशत सामान्यतया ७० प्रतिशत होता है। उसके अनुसार उत्तर प्रदेश की २०२५ की जनसंख्या लगभग २४ करोड़ में से लगभग १६.८० करोड़ मतदाता होने चाहिए। निर्वाचन आयोग कोई भी प्रक्रिया अपना ले यह संख्या इसके लगभग होनी चाहिए। यदि इससे चार या पांच करोड़ कम होगी तो विवाद पैदा होगा होी।

पाठकों को ज्ञात है कि एस आई आर की प्रक्रिया उन्हीं सरकारी कर्मचारियों के द्वारा की जा रही है जो इस प्रक्रिया में निर्वाचन आयोग के अधीन काम करते हैं। पहले भी लगभग उन्हीं कर्मचारियों में निर्वाचन आयोग के देखरेख में काम किया । जिस प्रकार से बहुत बड़ी संख्या में मतदाता सूची में नाम कटने की बात सामने आ रही है, उससे तो ऐसा लगता है कि पहले कर्मचारियों ने अपना काम किया ही नहीं। यदि इसे सही मान भी लें तो इस बात की क्या गारंटी है अभी जो कर्मचारी काम कर रहे हैं वे बिल्कुल सही कर रहे होंगे, क्योंकि कर्मचारी तो वही हैं । निर्वाचन आयोग ने अपने पूर्ववर्ती निर्वाचन आयोगों के काम पर प्रश्न चिन्ह लगाकर अपनी विश्वसनीयता को कम ही किया है।

इससे पहले कि एस आई आर का मुद्दा विपक्षी दलों और सत्ताधारी दलों के बीच बहुत बड़े घमासान का रूप ले ले, उचित होगा कि सर्वोच्च न्यायालय इसमें हस्तक्षेप करे और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने का काम करे,ताकि योग्य मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न हो जाएं।

—**अतिथि सम्पादक,**
राजेन्द्र भागवत (पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)

संपादकीय

मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राजस्थान बना एआई नवाचार का उभरता केंद्र

राजस्थान रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस भारत के समावेशी और सतत एआई विकास की मजबूत नींव



धर्मेन्द्र कुमार मीना

राजस्थान ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के क्षेत्र में राष्ट्रीय विजन को साकार करने की दिशा में एक और ठोस कदम बढ़ाया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान एआई नवाचार के उभरते केंद्र के रूप में

पहचान बना रहा है। राजस्थान क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट संदेश दिया कि तकनीक-आधारित विकास, समावेशी प्रगति और जनकल्याण के लिए एआई का उपयोग सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। यह सम्मेलन भारत एआई इम्पैक्ट समिट- २०२६ की तैयारी के क्रम में एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय पड़ाव सिद्ध हुआ।

सम्मेलन में संस्थागत सहयोग को नई ऊंचाई देते हुए गूगल, आईआईटी दिल्ली, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर तथा स्मिथक डेवलपमेंट नेटवर्क (वाधवानी फाउंडेशन) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। इस बहुपक्षीय साझेदारी का उद्देश्य एआई अनुसंधान, बड़े पैमाने पर कौशल विकास, नैतिक

एवं कानूनी ढांचे तथा नवाचार-आधारित इकोसिस्टम को मजबूत करना है, जिससे युवाओं के लिए नए अवसर सृजित होंगे और राज्य की डिजिटल क्षमताओं में वृद्धि होगी।

उच्चस्तरीय रणनीतिक सत्र में श्री अभिषेक सिंह, अतिरिक्त सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमइआईटीवाय), सीईओ-इंडियाएआई मिशन एवं महानिदेशक-एनआईसी, ने श्री विशाल धूपर, मैनेजिंग डायरेक्टर-साइथ एशिया, एनवीडिया के साथ संवाद किया। सत्र का संचालन श्री समीर जैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, प्राइमस पार्टनर्स ने किया। चर्चा में एआई अवसरचना के लोकतंत्रीकरण, सार्वजनिक-निजी भागीदारी को सुदृढ़ करने, नवाचार को व्यापक स्तर पर सक्षम बनाने तथा सुरक्षित और

भरोसेमंद एआई के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की क्षमता निर्माण जैसे विषयों पर विचार-विमर्श हुआ।

इंडियाएआई मिशन की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए कविता भाटिया, वैज्ञानिक ‘जी’, समूह समन्वयक, एमइआईटीवाय एवं सीओओ-इंडिया एआई मिशन ने भारत एआई इम्पैक्ट समिट २०२६ की दृष्टि और प्राथमिकताओं को रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि नीति, अवसरचना और मानव संसाधन विकास के समन्वित प्रयासों से एआई को जनकल्याण से जोड़ा जा रहा है।

वैश्विक एआई, राष्ट्रीय एआई और क्षेत्रीय एआई विषय पर अविनाश शर्मा, प्रोफेसर, आईआईटी जोधपुर ने क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थानों की भूमिका को प्रकाश डालते हुए कहा कि स्थानीय संदर्भों को समझने वाले समाधान ही

वैश्विक स्तर पर प्रभावी सिद्ध होते हैं। सम्मेलन के दौरान शासन, अवसरचना, नवाचार, नैतिकता और रोजगार जैसे विषयों पर समानांतर सत्र आयोजित किए गए, जिनमें एआई के व्यावहारिक अनुप्रयोगों और जनसेवा में इसके उपयोग पर चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राजस्थान सरकार की यह पहल राज्य को एआई आधारित नवाचार, कौशल विकास और सतत विकास का अग्रणी केंद्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। राजस्थान क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस ने यह सिद्ध किया कि राज्य तकनीक को जनहित से जोड़ते हुए भारत के एआई भविष्य में सक्रिय और प्रभावी भूमिका निभाने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है।

—**धर्मेन्द्र कुमार मीना,**
सहायक निदेशक, करौली

बांग्लादेश – एक ओर कटु अनुभव



प्रो. कैलाश सोडान्णी

१९४७ में भारत के साथ-साथ धर्म के आधार पर पाकिस्तान का भी एक राष्ट्र के रूप में उदय हुआ। पाकिस्तान को मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर दो भूखंड प्राप्त हुए, जिन्हें पश्चिमी एवं पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना गया। राजनैतिक एवं सैन्य नैतृत्व हमेशा पश्चिमी पाकिस्तान के पास रहा, परिणामस्वरूप पूर्वी पाकिस्तान हमेशा शोषित एवं पीड़ित ही रहा। पश्चिमी पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान के साथ भाषाई, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आधार पर बहुत अत्याचार किए उर्दू को राष्ट्र भाषा बनाने और बांग्ला को उपेक्षित करने से बंगालियों में भारी असंतोष रहा।

बजट का अधिकतम हिस्सा केवल पश्चिमी पाकिस्तान के विकास पर खर्च किया एवं पूर्वी पाक को

नजरअंदाज किया गया। जनसंख्या में अधिक होने के बावजूद पूर्वी पाक को राजनीतिक प्रतिनिधित्व बहुत कम दिया गया। पश्चिमी पाकिस्तान के जुल्मों के खिलाफ मुजीबुर्रहमान के नेतृत्व में जन आंदोलन ‘मुक्ति संग्राम’ प्रारम्भ हुआ। मार्च १९७१ में शेख मुजीबुर्रहमान को गिरफ्तार करके पाकिस्तानी सेना ने ‘ऑपरेशन सर्चलाइट’ शुरू किया, जिसके दौरान पाकिस्तानी सेना द्वारा व्यापक अत्याचार, नरसंहार और बलात्कार हुए।

१९७० के आम चुनावों में अवामी लीग की जीत के बावजूद पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं एवं सेना ने सत्ता सौंपने से इंकार कर दिया। यही से बांग्लादेश के जन्म की कहानी शुरू हुई। इन अत्याचारों के कारण लाखों लोगों ने भारत में शरण ली, जिससे एक बड़ा शरणार्थी संकट पैदा हुआ और यहीं से भारत का हस्तक्षेप प्रारम्भ हुआ। यह हस्तक्षेप अन्ततः भारत-पाक युद्ध (बांग्लादेश मुक्ति संग्राम) में परिवर्तित हुआ। १३ दिनों का युद्ध १६ दिसंबर, १९७१ को समाप्त हुआ।

जनरल मानेकशा के मजबूत एवं कुशल नेतृत्व में भारतीय सेना और बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी के सामने पाकिस्तानी सेना के ९३००० सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। १९७१ के भारत-पाक युद्ध की एक मात्र वजह पूर्वी पाकिस्तान को नगरिकों को पाकिस्तानी सेना के

अत्याचारों से मुक्ति दिलाना था। इस युद्ध में अमेरिका ने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया। अन्तर्राष्ट्रीय खतरों से खेलते हुए भारत ने पाक को धराशायी किया एवं पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश में बदल दिया। पूरी दुनिया ने बांग्लादेश के रूप में एक नये राष्ट्र के निर्माण में भारत के प्रत्यक्ष योगदान को स्वीकार किया। विश्व में बांग्लादेश को एक राष्ट्र के रूप में भारत ने ही सबसे पहले मान्यता प्रदान की। तब अन्य देशों ने बांग्लादेश को स्वीकार किया।

भारत सरकार ने बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान बांग्लादेश के वर्ष

वर्ष	भारत में मुसलमान	बांग्लादेश में हिन्दू
१९४१	९.८ प्रति.	२८.४ प्रति.
१९७१	११.२ प्रति.	१३.६ प्रति.
२०११	१३.४ प्रति.	८.५ प्रति.

शरणार्थियों की सहायता के लिए भारतीय जनता से दान एवं विशेष डाक टिकटों से धन एकत्रित किया। बांग्लादेश निर्माण में आम भारतीय नागरिकों का भी प्रत्यक्ष योगदान रहा है। भारत ने बांग्लादेश को हमेशा अपना छोटा भाई समझकर हर संभव मदद की। परन्तु दुर्भाग्य है कि यह भाई दुर्योगधन-दुशासन ही सिद्ध होता जा रहा है। बांग्लादेश को गैहूँ एवं चावल जैसे जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति भारत करता है। बांग्लादेश मुख्यरूप से दुनिया को रेडीमेड कपड़ों का निर्यात करके विदेशी मुद्रा अर्जित करता है जिसका

आधार भारतीय कपास एवं धागे ही हैं।

अघोषित हिन्दू राष्ट्र भारत बांग्लादेश को उसके जन्म से लेकर आज तक पल्लवित कर रहा है फिर भी वहाँ हिंदुओं की लगातार घटती आबादी उनके दुःख-दर्द की ही अभिव्यक्ति है। भारत में मुसलमानों की आबादी का लगातार बढ़ना यह सिद्ध करता है कि वे यहाँ पूर्ण शान्ति एवं प्रतिष्ठा से जीवन जी रहे हैं।

उक्त आंकड़े एवं तथ्य बहुत कुछ कह रहे हैं। इन आंकड़ों की पीछे छिपी हुई सच्चाई को समझना होगा। देश और

वर्ष	भारत में मुसलमान	बांग्लादेश में हिन्दू
१९४१	९.८ प्रति.	२८.४ प्रति.
१९७१	११.२ प्रति.	१३.६ प्रति.
२०११	१३.४ प्रति.	८.५ प्रति.

दुनिया के धार्मिक संतुलन में होने वाला यह परिवर्तन हमें किस दिशा में ले जाएगा इस पर चिन्तन होना चाहिये। धर्म निरपेक्षता तथा गंगा-जमुना तहजीब के नारों की आवाज में हमें हमारे इतिहास और आज की वास्तविकता को नजरंदाज नहीं करना चाहिये।

भारत हर बार एक ही गलती को दोहराता आ रहा है और उसके दुष्परिणाम भी भुगत रहा है, फिर भी सुधर नहीं रहा है। लोगों को पहचानने में हर बार की इस भूल से ही भारत टूटता गया, बिखरता गया और अपमानित होता गया। दुश्मन को बार-बार माफ करने की तथा कथित

छबड़ा में संचालित अन्नपूर्णा योजना की

रसोई में अनियमितताओं का आरोप

बताया जा रहा है कि रसोई पर काम करने वाले कर्मचारी मनमानी करते हैं

छबड़ा, (निसं)। राजस्थान सरकार की ‘कोई भूखा ना सोए’ योजना के तहत बस स्टैंड पर संचालित अन्नपूर्णा रसोई की व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। शहर में संचालित उक्त रसोई में न केवल लाभार्थियों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, बल्कि उन्हें एक-एक घंटे इंतजार कराने के बाद भी खाना नहीं दिया जा रहा है।

पिंकू, ओमप्रकाश, सत्यनारायण, राधेश्याम, फूलचंद, रामनिवास, नेमीचंद आदि ने आरोप लगाते हुए बताया कि इस रसोई पर काम करने वाले कर्मचारी अपनी मनमानी कर रहे हैं।

पिंकू, ओमप्रकाश, सत्यनारायण, राधेश्याम, फूलचंद, रामनिवास, नेमीचंद आदि ने आरोप लगाते हुए बताया कि इस रसोई पर काम करने वाले कर्मचारी अपनी मनमानी कर रहे हैं और खाना खाने आए लोगों को बेवजह परेशान कर रहे हैं। उन्हें घंटों इंतजार कराने के बाद भी भूख पेट वापस लौटना पड़ रहा है। कर्मचारी

- शहर में संचालित अन्नपूर्णा योजना रसोई में न केवल लाभार्थियों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, बल्कि उन्हें एक-एक घंटे इंतजार कराने के बाद भी खाना नहीं दिया जा रहा**
- आरोप है कि इस रसोई पर काम करने वाले कर्मचारी अपनी मनमानी कर रहे हैं और खाना खाने आए लोगों को बेवजह परेशान कर रहे हैं**

लाभार्थियों के साथ दादागिरी कर रहे हैं और उन्हें भोजन देने से इनकार कर रहे हैं। समीप में संचालित हो रहे रेन बसेरे में ठहरने वाले लोग जब रसोई

पर खाना खाने पहुंचते हैं तो उनके साथ अशोभीयता व्यवहार किया जाता है।

रसोइयों में पूरा भोजन नहीं दिया जा रहा
:- सरकार का उद्देश्य है कि हर व्यक्ति को भरपेट भोजन मिले। इसी वजह से दो साल पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर खाने की मात्रा बढ़ाई गई थी। पूर्ववर्ती सरकार के समय ४५० ग्राम भोजन मिलता था, जिसे बढ़ाकर भजनलाल सरकार ने ६०० ग्राम कर दिया। अन्नपूर्णा रसोइयों में ८ रुपए में एक थाली भोजन दिया जाता है। प्रत्येक थाली पर सरकार की ओर से

२२ रुपए का अनुदान दिया जाता है। भोजन की निर्धारित मात्रा प्रति थाली ६०० ग्राम है, लेकिन कई रसोइयों में पूरा भोजन नहीं दिया जा रहा है। नियमानुसार अन्नपूर्णा रसोइयों में पूरी साफ-सफाई होनी चाहिए और सम्मानजनक तरीके से खाना दिया जाना चाहिए। भोजन करने वाले हर व्यक्ति का फोटो खींचा जाता है, ताकि उसी हिसाब से संचालक सरकार को रिपोर्ट भेजें और फिर अनुदान की राशि स्वीकृत हो। हर रसोई में भोजन का मेन्यू चार्ट लगाया होना चाहिए।

राशिफल मंगलवार १३ जनवरी, २०२६	
	
	
	
पंडित अनिल शर्मा	
माघ मास, कृष्ण पक्ष, दशमी तिथि, मंगलवार, विक्रम संवत् २०८२, विशाखा नक्षत्र रात्रि १२:०७ तक, शूल योग सायं ७:०५ तक, विष्टि करण दिन ३:१८ तक, चन्द्रमा सायं ५:२१ से वृश्चिक राशि में संचार करेगा।	
गृह स्थिति: सूर्य-धनु, चन्द्रमा-तुला, मंगल-धनु, बुध-धनु, गुरू-मिथुन, शुक्र-मकर, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह	
आज कुमार योग रात्रि १२:०७ तक है। भद्रा दिन ३:१८ तक रहेगी। आज लोहड़ी उत्सव, भोगी (उ.भारत में) है।	
श्रेष्ठ चौघड़िया: चर ९:५८ से ११:१७ तक, लाभ-अमृत ११:१७ से १:५४ तक, शुभ ३:१२ से ४:३१ तक। राहुकाल: ३:०० से ४:३० तक। सूर्योदय ७:२१, सूर्यास्त ५:४९	

मेघ	
	
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में धार्मिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। व्यावसायिक वाला सफल रहेगी।	
वृष	
	
परिजनों/मित्रों से चल रहे आपसी मतभेद दूर होने लगेगे। विवाहित मामलों से राहत मिल सकती है। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।	
मिथुन	
	
व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। आज महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में अचित सोच-विचार हो सकता है।	
कर्क	
	
घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। अतिथियों का आगमन बना रहेगा। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होंगे।	

सिंह	
	
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। मित्रों/परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।	
कन्या	
	
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। संभावित ख़ोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी।	
तुला	
	
मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मन:स्थिति में सुधार होगा। आज आवश्यक कार्य योजनानुसार बनने लगेगे। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता अभी व्यक्तित्व बनी रहेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।	

धनु	
	
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। संभावित ख़ोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।	
मकर	
	
व्यावसायिक कार्यों को प्रयास करें। अटक हुए कार्य बरने लगेगे। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक मामलों में संतुलन बना रहेगा।	
कुंभ	
	
नवीन कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होंगे। अटक हुए कार्य बरने लगेगे। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।	
मीन	
	
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यक्तवान हो सकता है। आवश्यक कार्यों में विलम्बा हो सकता है। यात्रा में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।	



श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री



श्री भजनलाल शर्मा
माननीय मुख्यमंत्री

राजस्थान में

1 लाख सरकारी पदों की भर्ती परीक्षा का कैलेण्डर - 2026

क्र.सं.	परीक्षा का नाम	पदों की संख्या	परीक्षा माह
1	प्राध्यापक भर्ती - 2025	09	जनवरी
2	राजस्थान प्राथमिक विद्यालय अध्यापक (लेवल-I) सीधी भर्ती परीक्षा - 2025	5449	जनवरी
3	राजस्थान उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक (लेवल-II) (विज्ञान गणित) सीधी भर्ती परीक्षा - 2025	1043	जनवरी
4	राजस्थान उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक (लेवल- II) (सामाजिक अध्ययन) सीधी भर्ती परीक्षा - 2025	296	जनवरी
5	राजस्थान उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक (लेवल- II) (अंग्रेजी) सीधी भर्ती परीक्षा - 2025	221	जनवरी
6	राजस्थान उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक (लेवल- II) (हिन्दी) सीधी भर्ती परीक्षा - 2025	174	जनवरी
7	राजस्थान प्राथमिक विद्यालय अध्यापक (लेवल-I) (संस्कृत) सीधी भर्ती परीक्षा - 2025	187	जनवरी
8	राजस्थान उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक (लेवल-II) (संस्कृत) सीधी भर्ती परीक्षा - 2025	389	जनवरी
9	शिक्षा विभाग (विभिन्न पद)	10000	जनवरी - मार्च
10	सहायक विद्युत निरीक्षक भर्ती - 2025	09	फ़रवरी
11	कनिष्ठ रसायनज्ञ भर्ती - 2025	13	फ़रवरी
12	आयुष मिशन के विभिन्न पद	1548	फ़रवरी
13	सहायक अभियंता संयुक्त भर्ती - 2024 (मुख्य परीक्षा)	1014	मार्च
14	उप निरीक्षक पुलिस परीक्षा - 2025	1015	अप्रैल
15	कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती परीक्षा	1100	अप्रैल
16	पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती - 2025	1100	अप्रैल
17	सहायक कृषि अभियंता भर्ती - 2025	281	अप्रैल
18	प्रयोगशाला सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा (भूगोल)	136	मई
19	प्रयोगशाला सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा (विज्ञान)	668	मई
20	व्याख्याता, व्याख्याता कृषि एवं कोच संयुक्त भर्ती - 2025 (माध्यमिक शिक्षा)	3725	मई - जून
21	राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं (संयुक्त) परीक्षा	500	मई
22	महिला पर्यवेक्षक सीधी भर्ती परीक्षा	72	जून

क्र.सं.	परीक्षा का नाम	पदों की संख्या	परीक्षा माह
23	वनपाल सीधी भर्ती परीक्षा	259	जून
24	कानिस्टेबल परीक्षा	4000	जून-जुलाई
25	लिपिक ग्रेड-II/कनिष्ठ सहायक सीधी भर्ती परीक्षा	10644	जुलाई
26	वरिष्ठ अध्यापक संयुक्त भर्ती - 2025(माध्यमिक शिक्षा)	6500	जुलाई
27	कनिष्ठ विधि अधिकारी भर्ती - 2025	12	जुलाई
28	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (विभिन्न पद)	3000	जुलाई-अगस्त
29	वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक सीधी भर्ती परीक्षा	322	अगस्त
30	बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक सीधी भर्ती परीक्षा	2214	अगस्त
31	सांख्यिकी अधिकारी भर्ती - 2025	113	अगस्त
32	शारीरिक शिक्षा अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा	1079	सितम्बर
33	निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स भर्ती - 2025	12	सितम्बर
34	निरीक्षक कारखाना (रसायन) भर्ती - 2025	01	सितम्बर
35	सहायक निदेशक एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी भर्ती - 2025	09	अक्टूबर
36	सफाई कर्मचारी भर्ती	24793	अक्टूबर
37	ऊर्जा विभाग (विभिन्न पद)	2000	अक्टूबर
38	विविध पद	6000	अक्टूबर - दिसम्बर
39	संरक्षण अधिकारी भर्ती - 2025	12	नवम्बर
40	कनिष्ठ अभियंता संयुक्त सीधी भर्ती	774	नवम्बर
41	संविदा टीचिंग एसोसिएट सीधी भर्ती परीक्षा	3500	दिसम्बर
42	ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा	3430	दिसम्बर
43	चिकित्सा अधिकारी भर्ती	600	दिसम्बर
44	नर्सिंग एवं पैरा मेडिकल भर्ती	2000	दिसम्बर

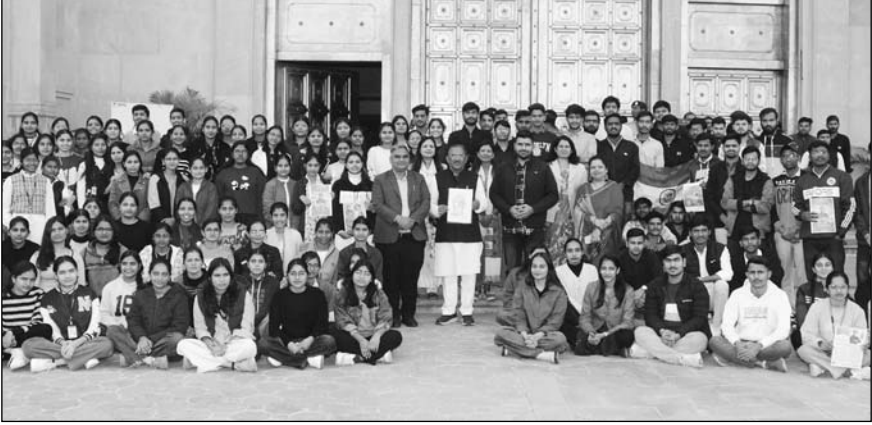
“प्रदेश के युवाओं को मेरी ओर से बहुत-बहुत शुभकामनाएं। सरकार निष्पक्ष, पारदर्शी एवं योग्यता के आधार पर भर्तियों के लिए कृतसंकल्प है। आपकी मेहनत एवं लगन, आपके और प्रदेश के उज्ज्वल भविष्य का निर्माण करेगी।”

- भजनलाल शर्मा, मुख्यमंत्री

युवा दिवस पर युवाओं ने देखी विधानसभा

विधान सभा में लगाये गये रक्तदान शिविर में 81 लोगों ने रक्तदान किया और 155 लोगों ने निःशुल्क मेडिकल जांच कराई

जयपुर। राष्ट्रीय युवा दिवस पर राजस्थान विश्वविद्यालय के विभिन्न महाविद्यालयों के युवाओं ने राजस्थान विधानसभा के सदन, भवन और संग्रहालय को देखा। देवनानी ने युवाओं का आह्वान किया कि वे निरन्तर मेहनत करें, आगे बढ़ें और राष्ट्र की प्रगति में सक्रिय भागीदार बने। देवनानी ने युवाओं को युवा दिवस की शुभकामनाएं देते हुए युवाओं को नशे की लत से दूर रहने और ओवर स्पीड से वाहन नहीं चलाने तथा यातायात नियमों का पालन करने के लिये कहा। युवाओं ने विधान सभा को देखने का अवसर प्रदान करने के लिए स्पीकर देवनानी का आभार जताया। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पहल पर शुरू किये गये जनदर्शन अभियान के तहत सोमवार को युवा दिवस पर महाविद्यालय शिक्षा के तीन सौ युवाओं ने विधान सभा देखी। राजस्थान विश्वविद्यालय के विभिन्न महाविद्यालयों में स्नातक अन्तिम वर्ष के युवाओं ने विधान सभा के गुलाबी सदन और ऐतिहासिक भवन को देखकर गौरव का अनुभव किया। युवाओं ने विधान सभा के राजनैतिक आख्यान संग्रहालय को भी



युवाओं ने विधान सभा को देखने का अवसर प्रदान करने के लिए स्पीकर देवनानी का आभार जताया।

देखा। युवाओं ने राज्य के गौरवशाली इतिहास को जाना। स्पीकर देवनानी को युवाओं ने अपने हाथों से बनाए स्वामी विवेकानन्द के चित्र भेंट किये। युवाओं ने देवनानी को जन्म दिवस की शुभकामनाएं भी दी। इस मौके पर दी अर्थ ऐसोसिएशन की डॉ. हेमलता शर्मा, भावना बंसल, नीतू कुशवाह और रिया हिम्मत रामका भी मौजूद थीं। देवनानी के जन्मदिवस पर विधानसभा सचिवालय कर्मचारी

बचत एवं साख सहकारी समिति के तत्वावधान में सोमवार को यहां विधान सभा में राजस्थान हॉस्पिटल व स्वास्थ्य कल्याण ब्लड बैंक द्वारा मानव कल्याण हेतु लगाये गये रक्तदान एवं निःशुल्क मेडिकल चेकअप शिविर में 81 लोगों ने रक्तदान किया और 155 लोगों ने निःशुल्क मेडिकल जांच कराई। शिविर में सोमवार को प्रातः 10 बजे से राजस्थान विधानसभा सचिवालय

में विधानसभा के अधिकारी-कर्मचारियों सहित बड़ी संख्या में लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। स्वेच्छा से रक्तदान कर मानव सेवा का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया। रक्तदाताओं को विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित भी किया। विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को राज्य मंत्री मण्डल के सदस्य सहकारिता मंत्री गौतम कुमार

■ स्पीकर देवनानी ने युवाओं को दी शुभकामनाएं और कहा मेहनत करो और आगे बढ़ो

दक ने पुष्प गुच्छ भेंट कर देवनानी को जन्म दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी।

देवनानी को विधायकगण रविन्द्र सिंह भाटी, रोहित बोहरा, जसवंत सिंह पूर्व विधायक जीतराम, रामकिशोर मीणा सहित अनेक जनप्रतिनिधिगण ने जन्म दिवस की बधाई दी। स्पीकर देवनानी को राजस्थान विधान सभा पहुंचने पर प्रमुख सचिव भारत भूषण शर्मा व विशिष्ट सहायक के. के. शर्मा के साथ विधान सभा के सभी अधिकारी और कर्मचारियों ने जन्मदिवस पर अभिवादन करते हुए उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। देवनानी से जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी के प्रो. वाईस चांसलर सुधीर भण्डारी, अक्षय पात्र के प्रतिनिधिगण और पत्रकारगण ने जन्म दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं दी।

जयपुर डिस्कॉम ने की पतंग उड़ते समय सावधानी बरतने की अपील

जयपुर। जयपुर डिस्कॉम ने मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने के दौरान बिजली की लाइनों से पर्याप्त दूरी बनाये रखने के साथ ही कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखने की अपील की है। यदि आवश्यक सतर्कता बरती जाए तो किसी भी संभावित विद्युत दुर्घटना से बचा जा सकता है एवं विद्युत आपूर्ति में व्यवधान की भी रोक जा सकती है। मकानों के पास से गुजर रही

बिजली की लाइनों के आस-पास पतंग उड़ाने समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। यदि बिजली के तारों अथवा उपकरणों में पतंग या डोर फंस जाए तो लोहे अथवा एल्यूमिनियम के पाइप, सिरिए या गीली लकड़ी से पतंग हटाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। एल्यूमिनियम फॉयल (धातु) से बनी हुई पतंग एवं मेटल पाउडर कोटेड मांझे का उपयोग नहीं करना चाहिए।

पुस्तक ‘सूर्य नमस्कार’ का विमोचन

जयपुर। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर विश्व चैंपियन संदीप आर्य द्वारा लिखित पुस्तक ‘सूर्य नमस्कार’ का विमोचन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ द्वारा किया गया। राठौड़ ने संदीप आर्य की उपलब्धियों की सराहना करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि संदीप आर्य देश और विदेश में सूर्य नमस्कार की अलख जगा रहे हैं, जो भारत की प्राचीन योग परंपरा को वैश्विक मंच पर स्थापित करने का

■ प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने विश्व चैंपियन संदीप आर्य द्वारा लिखित पुस्तक ‘सूर्य नमस्कार’ का विमोचन किया

महत्वपूर्ण कार्य है। राठौड़ ने संदीप के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए युवाओं से इस महाभियान से जुड़ने का आ आन किया। संदीप अब ‘सूर्य’ नमस्कार

महाभियान’ की शुरुआत कर रहा है। इसमें देशभर के 10 करोड़ युवाओं को सूर्य नमस्कार से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे स्वस्थ, सशक्त और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण किया जा सके।

उल्लेखनीय है कि संदीप आर्य ने सूर्य नमस्कार के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए लगातार 37 घंटे बिना रुके 20 हजार बार सूर्य नमस्कार कर अब तक 6 बार विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं।

‘एपीओ भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों सहित असफल हुए दस अभ्यर्थियों की काँपी करें पेश’

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने सहायक अभियोजन अधिकारी भर्ती-2024 में सिर्फ चार अभ्यर्थियों के पास होने के मामले में आरपीएससी को निर्देश दिए हैं कि वह इन चयनित अभ्यर्थियों सहित परीक्षा में असफल रहे किन्हीं 10 अन्य अभ्यर्थियों की काँपी अदालत में सीलबंद लिफाफे में पेश करें।

वहीं अदालत ने याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों की ओर से परीक्षा में प्राप्त किए गए कुल अंकों की जानकारी भी सारणीबद्ध तरीके से देने को कहा है। अदालत ने कहा है कि 15 जनवरी को आरपीएससी सचिव या उनकी ओर से मामले को जानने वाला अधिकृत सक्षम अधिकारी अदालत में हाजिर हो। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश सृष्टि सिंघल व अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान आरपीएससी के सचिव वीसी के जरिए अदालत से जुड़े। तकनीकी बाधा के चलते उनकी ओर से अदालत में संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। इस पर अदालत ने मामले की सुनवाई टालते हुए अभ्यर्थियों की काँपियां पेश करने के आदेश देते हुए

- याचिका में कहा गया कि आयोग की ओर से जारी यह परिणाम मनमाना, अव्यावहारिक और संविधान के मूल अधिकारों के खिलाफ है।
- अदालत ने मामले की सुनवाई टालते हुए अभ्यर्थियों की काँपियां पेश करने के आदेश देते हुए अधिकारी को तलब किया है

अधिकारी को तलब किया है। याचिका में अधिवक्ता तनवीर अहमद ने अदालत को बताया कि आरपीएससी ने सहायक अभियोजन अधिकारी के 180 पदों भर्ती निकाली थी। जिसमें मुख्य परीक्षा में करीब तीन हजार अभ्यर्थी शामिल हुए। परीक्षा में एक प्रश्न पत्र विधि और एक प्रश्न पत्र हिंदी व अंग्रेजी भाषा का रखा गया था। लिखित परीक्षा के बाद आयोग ने सिर्फ 4 अभ्यर्थियों को ही सफल घोषित किया और आयोग के परिणाम के अनुसार अन्य सभी अभ्यर्थी न्यूनतम अनिवार्य चालीस फीसदी अंक भी नहीं ला सके। याचिका में कहा गया कि भर्ती परीक्षा में शामिल कई अभ्यर्थी ऐसे भी हैं, जिन्होंने राजस्थान न्यायिक सेवा परीक्षा में चालीस फीसदी से

अधिक अंक हासिल किये थे। आरजेएस परीक्षा सहायक अभियोजन अधिकारी भर्ती परीक्षा से कहीं अधिक कठिन परीक्षा मानी जाती है। इसके बावजूद ऐसे अभ्यर्थियों को इस परीक्षा में असफल कर दिया गया। याचिका में कहा गया कि आयोग की ओर से जारी यह परिणाम मनमाना, अव्यावहारिक और संविधान के मूल अधिकारों के खिलाफ है। याचिका में आशंका जताई गई है कि परीक्षा के मूल्यांकन में त्रुटिपूर्ण मॉडल उत्तर और अत्यधिक कठोर अंकन कर मपीवी अंशज में काँपियां जांची गई हैं। ऐसे में परीक्षा परिणाम को रद्द कर नए सिरे उत्तर पुस्तिकाओं की जांच कर संशोधित परिणाम जारी किया जाए।

■ कार्यक्रम में 95 स्वयंसेवकों ने घोष वादन किया, जिसे सुनकर बड़ी संख्या में उपस्थित समाजबंधु मंत्रमुग्ध हो गए

में उपस्थित समाजबंधु मंत्रमुग्ध हो गए। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय शारीरिक प्रमुख जगदीश रहे। उन्होंने युवा दिवस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि संघ अनेक उतार-चढ़ाव, प्रतिबंध और दमन का सामना करते हुए जागरण, पर्यावरण संरक्षण, नागरिक शिष्टाचार और कुटुम्ब प्रबोधन। उन्होंने कहा कि केवल सत्ता से नहीं, बल्कि



युवा दिवस के अवसर पर मानसरोवर जिला द्वारा वैशाली नगर में घोष का संचलन एवं प्रदर्शन किया।

जिसके बाद व्यापक गृह संपर्क अभियान चलाया गया।

इसका उद्देश्य समाज जागरण के लिए भारत के प्रत्येक घर तक पहुंचना रहा। इसी क्रम में देशभर में विराट हिंदू सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। इन प्रयासों का केंद्र ‘पंच परिवर्तन’ है सामाजिक समरसता, स्व के भाव का जागरण, पर्यावरण संरक्षण, नागरिक शिष्टाचार और कुटुम्ब प्रबोधन। उन्होंने कहा कि केवल सत्ता से नहीं, बल्कि

समाज के जागरण से ही परिवर्तन संभव है और इसका आधार परिवार है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रसिद्ध गीतकार राजेंद्र गुप्ता रहे। उन्होंने युवाओं से राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। इस अवसर पर महानगर संचालक चैन सिंह तथा जिला संचालक मान सिंह भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में समाज के विभिन्न वर्गों की उल्लेखनीय भागीदारी रही।

कृषि भूमि पर स्टांप ड्यूटी विवाद पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने शहरी क्षेत्र में स्थित कृषि भूमि पर आवासीय दर से स्टांप ड्यूटी वसूलने से जुड़े मामले में प्रमुख वित्त सचिव और आईजी स्टांप व कोटा उप-पंजीयक को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। एक्टिंग सीजे एसपी शर्मा और जस्टिस संगीता शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश दुर्गा शंकर की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता सिद्धार्थ बापना ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता की कोटा में कृषि भूमि है। जिसे राजस्व रिकॉर्ड में कृषि भूमि ही दर्शाया गया है और सरकार की ओर से इस पर कृषि दर से ही राजस्व वसूला जाता है। याचिकाकर्ता ने गत एक तिस्तंबर को इसे बेचने के लिए इकरारनामा किया था। इसके तहत भूमि को कृषि भूमि मानकर कीमत तय की गई और एक नवंबर, 2025 तक पूरी रकम अदा होने पर रजिस्ट्री कराने का निर्णय लिया गया। याचिका में कहा गया कि इस बीच 1 अक्टूबर को राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर कृषि भूमि की सीमा एक हजार वर्ग मीटर से बढ़ाकर दो हजार वर्ग मीटर कर दी। वहीं इसे स्टांप ड्यूटी के लिए आवासीय भूमि के समान मान लिया। याचिका में कहा गया कि यह फैसला

■ अधिवक्ता सिद्धार्थ बापना ने बताया कि याचिकाकर्ता की कोटा में कृषि भूमि है। जिसे राजस्व रिकॉर्ड में कृषि भूमि ही दर्शाया गया है और सरकार की ओर से इस पर कृषि दर से ही राजस्व वसूला जाता है

संविधान के प्रावधानों के खिलाफ है। वहीं संबंधित भूमि कृषि भूमि ही है और उसका न तो रूपांतरण हुआ है और ना ही भू उपयोग बदला गया है। इसके बावजूद उसे आवासीय मानकर अतिरिक्त स्टांप ड्यूटी वसूलना गलत है। इसके अलावा राज्य सरकार ने यह अधिसूचना जारी करने से पहले इस पर आपत्तियां नहीं मानी। ऐसे में पूर्व में किए गए समझौते इस अधिसूचना से प्रभावित हो रहे हैं। याचिका में गुहार की गई है कि इस अधिसूचना के संबंधित प्रावधान को रद्द किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।



रामकृष्ण मिशन, जयपुर ने कई दिलचस्प कार्यक्रमों के साथ राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया। युवा भाषण प्रतियोगिता में 18-25 साल के प्रतिभागियों ने भाग लिया। भाषण प्रतियोगिता 6 दिसंबर 2024 को आयोजित प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार दिए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आईएएस अधिकारी अनुपमा जोरवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रेया गुहा उपस्थित रही।

कांग्रेसियों का सिर्फ जनता को भ्रमित करने का प्रयास : मदन राठौड़

■ कांग्रेस कर रही हल्की राजनीति, बिना सोच वाली राजनीतिक पार्टी कांग्रेस दे रही है भ्रष्टाचारियों का साथ : मदन राठौड़

किया तो क्या गलत किया?। इतना ही नहीं, मोदी ने मजदूरी का भुगतान 15 दिवस में करने का काम किया तो क्या गलत किया? राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता जहाँ विरोध करना चाहिए, वहाँ विरोध नहीं जता रहे।

पश्चिम बंगाल में कोयला घोटाले मामले में ईडी की कार्रवाई को वहाँ की मुख्यमंत्री द्वारा प्रभावित किया जाता है, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को पपने तक नहीं दिया जा रहा, इसके बावजूद कांग्रेस वहाँ विरोध नहीं जता रही है। कांग्रेस नेता बिक्रुल हलकें स्तर की राजनीति पर उतर आए हैं। बिना सोच वाली राजनीतिक पार्टी कांग्रेस एक ओर

भ्रष्टाचारियों का साथ दे रही है, वहीं दूसरी ओर राष्ट्र प्रथम की भावना और विकसित भारत के सपने को पुरा करने की दिशा में कार्य करने वालों का विरोध कर रही है, यह समझ से परे है। कांग्रेसियों का विरोध भी दिखावा मात्र है, कहने को तो वे मौन अनशन पर थे, लेकिन उनके नेता मोबाइल पर बात कर रहे थे, मीडिया को बाइट दे रहे हैं, फिर कैसा मौन अनशन? भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि वीबी जी राम जी ने प्रत्येक ग्रामीण परिवार को अब प्रति वर्ष 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। मजदूरी का भुगतान कार्य समाप्ति के अधिकतम 15 दिनों के भीतर करना अनिवार्य किया गया, देरी होने पर मुआवजे का प्रावधान किया गया।

ग्राम पंचायतों और ग्राम सभाओं को योजना बनाने और कार्यान्वयन में मुख्य जिम्मेदारी दी गई है। केवल शारीरिक श्रम ही नहीं, बल्कि कौशल विकास, स्वरोजगार और उद्यमता पर भी विशेष जोर दिया गया है।

सार-समाचार

पचासवीं वर्षगांठ मनाई



जयपुर। पचास वर्ष पहले महाराजा के स्नातकों के स्वर्ण जयंती समारोह का प्रारंभ हुआ। जिससह हाइवे बनिपाक स्थित गुलाबी नगरी में ये स्वर्ण जयंती समारोह का जश्न मनाया गया।

बेयर फुट कॉलेज में सोलर दीदी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन



जयपुर। ग्रामीण महिलाओं की तकनीकी क्षमता निर्माण और विकेन्द्रीकृत व सतत सौर ऊर्जा समाधानों को जमीनी स्तर पर बढ़ावा देने के उद्देश्य से बेयर फुट कॉलेज में सोमवार को सोलर दीदी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यह कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ ऊर्जा आधारित आजीविका सृजन एवं महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में सिल्वीरा ब्लॉक की 30 स्वयं सहायता समूह महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित की गई है। सभी प्रतिभागी महिलाओं का चयन निर्धारित मानकों के अनुसार एसएचजी नेटवर्क से किया गया है तथा उन्हें आवासीय प्रशिक्षण हेतु बेयर फुट कॉलेज में नामांकित किया गया है। सोलर दीदी प्रशिक्षण कार्यक्रम को 40 दिवसीय संरचित मॉड्यूल के रूप में डिजाइन किया गया है, जिसमें सौर ऊर्जा के सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक दोनों पहलुओं पर विशेष बल दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को सौर ऊर्जा की मूलभूत अवधारणाओं, अनुप्रयोगों, सोलर पैनेल असेंबली एवं इंस्टॉलेशन, सौर उपकरणों के अनुस्क्षण एवं लघु मरम्मत, फील्ड स्तर पर ट्रबलशूटिंग तथा समुदाय-स्तरीय सौर प्रणालियों के प्रबंधन से संबंधित व्यवहारिक ज्ञान एवं कौशल प्रदान किया जाएगा।

मनीष केडिया शहर मीडिया प्रभारी मनोनीत

जयपुर। अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन, राजस्थान के जयपुर जिला अध्यक्ष सुधीर नाटाणी एवं जयपुर शहर महामंत्री विष्णु बिजानी की संस्तुति पर संजय कॉलोनी शिवपथ जयपुर निवासी मनीष केडिया को शहर मीडिया प्रभारी के पद पर मनोनीत किया गया केडिया की नियुक्ति पर श्रीराम अग्रवाल, सुनील अग्रवाल सहित अन्य बंधुओं ने शुभकामनाएं एवं बधाई दी।

पौष बड़ा महोत्सव का भव्य आयोजन

जयपुर । अखिल भारतीय हरियाणा गौड़ ब्राह्मण महासभा, जयपुर युवा संघ के तत्वावधान में जयपुर स्थित हरियाणा गौड़ ब्राह्मण छात्रावास पर नववर्ष स्नेह मिलन समारोह, पौष बड़ा महोत्सव एवं सुंदरकांड पाठ का भव्य एवं यादगार आयोजन हुआ। कार्यक्रम में भक्ति, प्रेम, का अद्भुत संगम देखने को मिला सभी समाज बंधुओं ने मिलजुलकर राम भक्ति में डूबकर सुंदरकांड का समूहिक पाठ किया जिससे पूरा माहौल आध्यात्मिकता से ओतप्रोत हो गया। युवा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सुनील टीलावाला ने बताया कि छात्रावास का वातावरण पूरी तरह भक्ति एवं स्नेह से भर गया था नववर्ष के स्वागत में हर्षोल्लास के साथ स्नेह मिलन हुआ।

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। जयपुर शहर में बरसात के दौरान जलभराव की समस्या के स्थाई समाधान और ड्रेनेज सिस्टम को सुदृढ़ बनाने की दिशा में जयपुर विकास प्राधिकरण ने एक बड़ी पहल की है। सोमवार को जयपुर विकास आयुक्त सिद्धार्थ महाजन की अध्यक्षता

■ सांगानेर और पृथ्वीराज नगर दक्षिण के लिए 250 करोड़ की कार्ययोजना की जायेगी तैयार

में जेडीए के चिंतन सभागार में डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर बैठक संपन्न हुई।

बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि अब जयपुर शहर के ड्रेनेज तंत्र को मजबूत करने के लिए जेडीए, नगर निगम और राज्य का आपदा प्रबंधन विभाग संयुक्त रूप से कार्य करेंगे।

बैठक में जेडीसी सिद्धार्थ महाजन ने निर्देश दिए कि तीनों विभाग आपसी समन्वय के साथ जयपुर शहर के लिए



जयपुर विकास आयुक्त सिद्धार्थ महाजन की अध्यक्षता में जेडीए के चिंतन सभागार में डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर बैठक संपन्न हुई।

एक मेजर कॉम्प्रिहेंसिव प्लान तैयार करें। इस योजना के क्रियान्वयन और वित्तीय प्रबंधन के लिए एक विशेष फंड भी बनाया जाएगा।

इस फंड में एसडीएमएफ के निर्धारित फंड के अलावा जेडीए और नगर निगम द्वारा भी राशि का योगदान दिया जाएगा।

योजना के सफल संचालन और तकनीकी निगरानी के लिए जेडीए, नगर निगम और आपदा प्रबंधन विभाग के अभियंताओं की एक संयुक्त कमेटी गठित की जाएगी, जो इस संपूर्ण कार्ययोजना का प्रबंधन संभालेगी।

बैठक में जानकारी दी गई कि

जेडीए द्वारा वर्तमान में प्राथमिकता के आधार पर सांगानेर और पृथ्वीराज नगर योजना दक्षिण क्षेत्र में ड्रेनेज और आपदा प्रबंधन के लिए 250 करोड़ रुपये की कार्ययोजना तैयार की जा रही है। यह कार्ययोजना नेबर्कन (नाबाई कंसल्टिंग सर्विसेज) के माध्यम से बनाई गई है।

